

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ

“युगनिर्माता : नरेंद्र दामोदर दास मोदी”

नरेंद्र दामोदरदास मोदी आधुनिक भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसे महानायक के रूप में उभरे हैं, जिन्हें ‘युगनिर्माता’ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। 21वीं सदी के भारत के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय है।



प्रारंभिक जीवन और संघर्ष

17 सितंबर, 1950 को गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और सेवा की प्रतिमूर्ति रहा है। वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर देश के प्रधान सेवक बनने तक का उनका सफर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन कौशल सीखा।

गुजरात का कायाकल्प: सुशासन का मॉडल

2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने ‘गुजरात मॉडल’ पेश किया। उन्होंने बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए। ‘वाइब्रेंट गुजरात’ जैसे आयोजनों के माध्यम से उन्होंने राज्य को निवेश का केंद्र बनाया।

प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक निर्णय

2014 और फिर 2019 में ऐतिहासिक जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का मंत्र दिया। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी:

- धारा 370 का उन्मूलन: कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ना।
- डिजिटल इंडिया: भारत को तकनीकी रूप से सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
- स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देना।
- आत्मनिर्भर भारत: रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाना।

वैश्विक मंच पर भारत का उदय

मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अधिक प्रखर हुई है। योग को वैश्विक मान्यता दिलाने से लेकर G20 की अध्यक्षता तक, उन्होंने भारत को ‘विश्व मित्र’ के रूप में स्थापित किया है। आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है।

नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर हैं जो 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका जीवन और कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।



मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का विस्तृत विवरण

मोदी सरकार की उपलब्धिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक (2014-2025) में अभूतपूर्व प्रगति की है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ मोदी सरकार ने देश के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक ढांचे में व्यापक बदलाव किए हैं।

1. आर्थिक सुधार और विकास (Economic Reform)

भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

GST का कार्यान्वयन :- 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा के साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना एक ऐतिहासिक सुधार रहा।

डिजिटल इंडिया और UPI :- भारत आज डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। UPI (Unified Payments Interface) ने बैंकिंग को हर नागरिक की जेब तक पहुँचा दिया है।

मेक इन इंडिया :- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'PLI स्कीम' शुरू की गई, जिससे भारत मोबाइल और रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बना है।

2. बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)

पीएम गति शक्ति बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान शुरू किया गया।

राजमार्ग और एक्सप्रेसवे प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स मील का पत्थर हैं। रेलवे का कायाकल्प वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास (अमृत भारत स्टेशन योजना) सराहनीय है।

3. सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन (Social Welfare)

सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से विचौलियों को खत्म कर सीधे गरीबों की मदद की है।

पीएम आवास योजना :- करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए।

उज्ज्वला योजना :- महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाने के लिए 10 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।



जल जीवन मिशन:- 'हर घर नल से जल' योजना के तहत ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल पहुँचाया जा रहा है।

आयुष्मान भारत: यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है।

4. आंतरिक और बाह्य सुरक्षा (National Security)

धारा 370 का खात्मा :- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे मुख्यधारा से जोड़ना एक ऐतिहासिक साहसिक निर्णय था।

आतंकवाद पर कड़ा प्रहार :- सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने 'घर में घुसकर मारने' की नीति अपनाई।

रक्षा आत्मनिर्भरता :- भारत अब स्वदेशी 'तेजस' विमान और 'आईएनएस विक्रान्त' जैसे युद्धपोत बना रहा है।

5. सांस्कृतिक पुनर्जागरण

(Cultural Renaissance)

मोदी सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया।

राम मंदिर निर्माण :- अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है।

काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक :- धार्मिक स्थलों का भव्य पुनर्विकास किया गया।

योग का वैश्विक विस्तार :- प्रधानमंत्री के प्रयासों से 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मान्यता मिली।

6. विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व

(Foreign Policy)

G20 की अध्यक्षता (2023) :- भारत ने सफलतापूर्वक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज बनकर उभरा। सशक्त भारत: यूक्रेन-रूस युद्ध या अन्य वैश्विक संकटों के दौरान भारत की तटस्थ और शांतिपूर्ण नीति की दुनिया भर में सराहना हुई।

7. महिला सशक्तिकरण और युवा

(Women & Youth)

नारी शक्तिबंदन अधिनियम :- संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कानून पारित किया गया।

मुद्रा योजना :- युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन की सुविधा प्रदान की गई।

निष्कर्ष :-

मोदी सरकार की उपलब्धियां केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर (Ease of Living) में सुधार किया है। 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ, सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीक और मानवीय विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों की दृढ़ इच्छाशक्ति ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है।

स्टार्टअप इंडिया

भारत सरकार ने देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी, 2016 को 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस कार्य योजना (Action Plan) में 19 सूत्रीय एजेंडा शामिल है, जिसे तीन प्रमुख स्तंभों के इर्द-गिर्द संरचित किया गया है: सरलीकरण और सहयोग, वित्त पोषण और प्रोत्साहन, और उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इन्क्यूबेशन।



**नववर्ष 2026 के हार्दिक शुभ अवसर पर
सभी देशवासियों को
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं**

**भूपेन्द्र सैनी
प्रदेश महामंत्री
भाजपा राजस्थान
पूर्व मंत्री
राजस्थान सरकार**

मुख्य स्तंभ और कार्य योजना

'स्टार्टअप इंडिया' कार्य योजना ने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित किया है। इसके प्रमुख स्तंभों का विवरण इस प्रकार है:

1. सरलीकरण और सहयोग (Simplification and Handholding)

इस स्तंभ का उद्देश्य नियामक बाधाओं को कम करना और स्टार्टअप्स के लिए परिचालन को आसान बनाना है। स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन स्टार्टअप्स को श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन की अनुमति है। शुरुआती तीन वर्षों तक श्रम कानूनों के तहत कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है।

मोबाइल ऐप और पोर्टल :- स्टार्टअप्स के लिए एक एकल संपर्क बिंदु (Single Point of Contact) के रूप में एक मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल शुरू किया गया, जो पंजीकरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न हितधारकों से जुड़ने में मदद करता है।

कानूनी सहायता और आईपीआर सुरक्षा :- स्टार्टअप्स को कम लागत पर पेटेंट फाइलिंग और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और शुल्क में 80% तक की छूट दी गई है।



सार्वजनिक खरीद के मानदंड :- सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए स्टार्टअप्स हेतु अनुभव या टर्नओवर मानदंडों में छूट दी गई है, जिससे उन्हें बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ समान अवसर मिलते हैं।

आसान निकास प्रक्रिया :- दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत, सरल ऋण संरचना वाले स्टार्टअप्स को 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद करने की अनुमति है, जिससे उद्यमियों को विफलता के मामले में पूंजी फंसाए बिना नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलता है।



2. वित्त पोषण और प्रोत्साहन

(Funding Support and Incentives)

यह स्तंभ सुनिश्चित करता है कि नवोन्मेषी विचारों वाले स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले।

फंड ऑफ फंड्स (FFS) सरकार ने नवाचार-संचालित उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ के कोष के साथ एक 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' स्थापित किया है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) 19 अप्रैल, 2021 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास और बाजार में प्रवेश के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता (अनुदान के रूप में ₹. 20 लाख तक और ऋण के रूप में ₹. 50 लाख तक) प्रदान करना है।

क्रेडिट गारंटी योजना :- स्टार्टअप्स को बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है।

कर लाभ :- पात्र स्टार्टअप्स को तीन लगातार वित्तीय वर्षों के लिए आयकर से छूट प्राप्त है। यह छूट इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मिलती है।

3. उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इन्क्यूबेशन (Industry & Academia Partnership and Incubation)

इस स्तंभ का लक्ष्य देश भर में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इन्क्यूबेशन केंद्र :- राष्ट्रीय संस्थानों (IITs, NITs, IIMs, आदि) में नवाचार और उद्यमिता के लिए 31 से अधिक केंद्र स्थापित /स्केल-अप किए गए हैं।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) :- इसके तहत देश भर के स्कूलों और संस्थानों में नवाचार से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

MENTORSHIP (MAARG) :- MAARG (Mentorship) एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस एंड ग्रोथ) प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स

और मेंटर्स के बीच बुद्धिमानी से मिलान की सुविधा प्रदान करता है।

अनुसंधान पार्क :- अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न IITs, में नए अनुसंधान पार्कों को समर्थन दिया जा रहा है।

उपलब्धियाँ और प्रभाव :- 'स्टार्टअप इंडिया' पहल ने भारत के स्टार्टअप परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स 15 जनवरी, 2025 तक, DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर 1,59,157 हो गई है।

रोजगार सृजन इन स्टार्टअप्स ने 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

यूनिकॉर्न की संख्या :- भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, जिसमें 2024 की शुरुआत तक 115 से अधिक यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनियाँ) हैं।

व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) :- भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग 2016 में 130 से बढ़कर 2020 में 63 हो गई, जिससे स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बना है।

निष्कर्ष:

'स्टार्टअप इंडिया' कार्य योजना केवल सरकारी सहायता से कहीं अधिक है: यह एक आंदोलन है जिसने भारतीय युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित किया है। सरलीकृत प्रक्रियाओं, वित्तीय सहायता और इन्क्यूबेशन समर्थन के संयोजन ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहाँ नवोन्मेषी विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद, इस पहल ने भारत को वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

आकृति प्रिंट द्वारा मुद्रिक कूप दे मैत्रे प्राइवेट लिमिटेड का आंतरिक समाचार पत्र

अभिषेक सक्सेना (एडिटर) मो.: 8696651687, 9509296259